भारतीय कानून रिपोर्ट

जे. वी. गुप्ता, जे. के समक्ष।

चंपा और ☒ न्य,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य, - प्रतिवादी।

1988 का नागरिक संशोधन संख्या 371

3 मार्च 1989.

भूमि ☒ धिग्रहण ☒ धिनियम (1894 का 1)- धारा 18, 28- ए- याचिकाकर्ता मुआवजे में वृद्धि के लिए आवेदन दाखिल नहीं कर रहा है- उसके सह- हिस्सेदार की याचिका पर मुआवजा बढ़ाया गया- याचिकाकर्ता ☒ दालत में जाने से पहले बढ़े हुए मुआवजे का दावा कर रहा है- धारा 28 ए के तहत उपचार के लिए सहारा नहीं लिया गया - निष्पादन न्यायालय को राहत देने की शक्ति।

माना गया कि भूमि ☒ धिग्रहण ☒ धिनियम, 1894 की धारा 28 ए प्रदान करके, विधायिका ने बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के लिए सहभागियों के ☒ धिकार को वैधानिक मान्यता दी है और बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया भी प्रदान की गई है। उक्त प्रक्रिया के तहत आवेदन कलेक्टर के समक्ष विचारणीय है न कि निष्पादन न्यायालय के समक्ष। चूँकि याचिकाकर्ताओं ने ☒ धिनियम की धारा 28 ए के तहत उपाय का लाभ नहीं उठाया, इसलिए

निष्पादन न्यायालय ने इस पर विचार करने से उचित रूप से इनकार कर दिया क्योंकि यह इस तरह से बनाए रखने योग्य नहीं था।

(पैरा 4,5)

श्री आर. सी. कथूरिया, ☒ तिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल की ☒ दालत के 4 सितंबर, 1987 के आवेदन को खारिज करने के आदेश के पुनरीक्षण के लिए धारा 115 सी.पी.सी. के तहत याचिका।

दावा: धारा 151 सी.पी.सी. के तहत आवेदन

पुनरीक्षण में दावा:-निचली ☒ दालत के आदेश को उलटने के लिए।

याचिकाकर्ताओं के वकील एस. पी. लल्लोर।

निमो, उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

(1) यह आदेश सिविल रिवीजन क्रमांक 372 सन् 1983 का भी निराकरण करेगा, क्योंकि दोनों प्रकरणों में प्रश्न समान है।

(2) हरियाणा सरकार ने ☒ धिसूचना, दिनांक 17 ☒ क्टूबर, 1978 के माध्यम से करनाल की नगरपालिका सीमा के भीतर स्थित भूमि का ☒ धिग्रहण किया, जिसके लिए भूमि ☒ धिग्रहण कलेक्टर ने 2 जून, 1982 को ☒ पना पुरस्कार दिया। फत्ता के पुत्रों हरि सिंह, शमशेर सिंह, लाई

सिंह ने भूमि ☒धिग्रहण ☒धिनियम (इसके बाद ☒धिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 18 के तहत एक संदर्भ दायर किया, जिसे ☒ंततः ☒तिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल ने 1 मई 1987 के आदेश के तहत स्वीकार कर लिया। और कानून के तहत प्रावधानित व्यवस्था और ब्याज के साथ 30 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से मुआवजा दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने खुद को जमीन का मालिक होने का दावा किया लेकिन ☒धिनियम की धारा 18 के तहत कोई संदर्भ दाखिल नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने इस प्रार्थना के साथ आवेदन दायर करके निष्पादन न्यायालय के ☒धिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया कि उन्हें भी उसी भूमि में सह-हिस्सेदार होने के नाते बढ़े हुए मुआवजे का लाभ दिया जाए। उक्त आवेदन को कार्यकारी न्यायालय द्वारा 4 सितंबर, 1987 के आक्षेपित आदेश के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि विचाराधीन भूमि 17 ☒क्टूबर, 1978 को ☒धिग्रहित की गई थी और यह पुरस्कार भूमि ☒धिग्रहण कलेक्टर द्वारा 2 जून 1982 को प्रदान किया गया था, जबकि वर्तमान आवेदन 22 मई 1987 को दायर किया गया है। ☒धिनियम की धारा 18, 18-ए, 19, 20 और 28 ए नामक विभिन्न प्रावधानों से उत्पन्न कानून की स्थिति यह है कि आवेदन धारा 151 सी.पी.सी. के तहत रखरखाव योग्य नहीं था।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सह-हिस्सेदार होने के नाते उसी मुआवजे के हकदार थे जो ☒न्य सह-हिस्सेदारों के उदाहरण पर ☒धिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ पर बढ़ाया गया था। इस प्रकार, विद्वान वकील ने तर्क दिया, कार्यकारी ☒दालत के समक्ष दायर आवेदन विचारणीय था। ☒पने तर्क के समर्थन में उन्होंने ***<u>हरियाणा राज्य बनाम</u>***

बिशन सिंह और ☒ न्य[1] , पंजाब राज्य बनाम मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड और ☒ न्य[2] का हवाला दिया। और ***श्री हरमंत सिंह और☒ न्य बनाम भूमि☒ धिग्रहण कलेक्टर, गुड़गांव[3]*** उन्होंने ***मेवा राम बनाम हरियाणा राज्य[4] (4), न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और☒ न्य बनाम भारत संघ[5] (5), और कलेक्टर, यू.टी. चंडीगढ़ बनाम श्रीमती, धन्नो (मृतक)[6] (6)*** जैसे प्राधिकारियों को ☒ लग करने की भी कोशिश की , लागू आदेश के समर्थन में निष्पादन न्यायालय द्वारा भरोसा किया गया।

(4) माना जाता है कि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था कि हिस्सेदार वे व्यक्ति हैं जिनकी भूमि उसी ☒ धिसूचना के तहत ☒ धिग्रहित की गई थी, वे बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं जो ☒ न्य दावेदारों को दिया जाता है। भूमि ☒ धिग्रहण ☒ धिनियम में, यथासंशोधित, धारा 28-ए जोड़ी गई और इसे निम्नानुसार प्रदान किया गया: -

"28-ए. न्यायालय के निर्णय के आधार पर मुआवजे की राशि का पुनर्निर्धारण।–(1) जहां इस भाग के तहत एक पुरस्कार है, न्यायालय आवेदक को धारा 11 के तहत कलेक्टर द्वारा दी गई

---

[1] **(1) 1981 पी.एल.जे. 40.**

[2] **(2) 1981 पी.एल.जे. 73.**

[3] **(3) 1987(2) पी.एल.आर. 188.**

[4] **(4) ए.आई.आर. 1987 एस.सी. 45.**

[5] **(5) 1987(1) पी.एल.आर. 578.**

[6] **(6) 1987(2) पी.एल.आर. 153.**

राशि से ⊠धिक किसी भी मुआवजे की राशि की ⊠नुमति देता है। ,धारा 4, उपधारा (1) के तहत समान ⊠धिसूचना के ⊠ंतर्गत आने वाली ⊠न्य सभी भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्ति और जो कलेक्टर के पुरस्कार से व्यथित हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने धारा 18 के तहत कलेक्टर को कोई आवेदन नहीं दिया था, कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर, निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर न्यायालय को यह ⊠पेक्षा करनी होगी कि उन्हें देय मुआवजे की राशि न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि के आधार पर फिर से निर्धारित की जाए:

बशर्ते कि तीन महीने की ⊠वधि की गणना करने में, जिसके भीतर इस उपधारा के तहत कलेक्टर को आवेदन किया जाएगा, जिस दिन पुरस्कार घोषित किया गया था और पुरस्कार की एक प्रति प्राप्त करने के लिए ⊠पेक्षित समय को बाहर रखा जाएगा।

(2) कलेक्टर, उपधारा (1) के तहत एक आवेदन प्राप्त होने पर, सभी इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस देने और उन्हें सुनवाई का उचित ⊠वसर देने के बाद जांच करेगा और आवेदकों को देय मुआवजे की राशि का निर्धारण करते हुए एक पुरस्कार बनाएं।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसने उपधारा (2) के तहत पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा, यह मांग कर सकता है कि मामला न्यायालय के निर्धारण के लिए कलेक्टर द्वारा भेजा जाए और धारा 18 से 28 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, ऐसे संदर्भ पर लागू होंगे जैसे वे धारा 18 के तहत एक संदर्भ पर लागू होते हैं।"

दूसरे शब्दों में, ☒ धिनियम की धारा 28-ए प्रदान करके इसे वैधानिक मान्यता दी गई और बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया भी प्रदान की गई। उक्त प्रावधान के तहत आवेदन कलेक्टर के समक्ष विचारणीय है न कि निष्पादन न्यायालय के समक्ष। बिशन सिंह के मामले (सुप्रा) और मैसर्स ग्लोब मोटर्स केस (सुप्रा) पर इस न्यायालय द्वारा पहले ***पंजाब राज्य बनाम श्रीमती तेज कौर*** *(7)* में विचार किया गया था, और प्रतिष्ठित किया गया था। मेसर्स ग्लोब मोटर्स मामले (सुप्रा) में एकमात्र मुद्दा यह उठाया गया था कि चूंकि केवल एक शेयरधारक ने ☒ धिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ का दावा किया था, बाकी शेयरधारक इसका लाभ नहीं लेंगे। इस विवाद को विद्वान एकल न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था, जिसे लेटर्स पेटेंट बेंच ने पुष्टि की थी। इसी तरह, बिशन सिंह के मामले (सुप्रा) में एकमात्र तर्क यह उठाया गया था कि दावेदार ☒ तिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा दिए गए पुरस्कार का लाभ नहीं उठा सकते थे क्योंकि उन्होंने संदर्भ नहीं मांगा था; ☒ धिनियम की धारा 18 के तहत केवल एक किस्सी के दावे के संबंध में कलेक्टर द्वारा संदर्भ दिया गया है। उक्त मामले में, माना जाता है कि संदर्भ में सभी सह-हिस्सेदारों के नाम थे, लेकिन आवेदन पर उनमें से एक द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। एकमात्र प्रासंगिक मामला श्री हरमंत का मामला (सुप्रा) है जहां निष्पादन न्यायालय के समक्ष ऐसा आवेदन किया गया था लेकिन संशोधित धारा 28-ए के प्रभाव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि धारा 18 के तहत संदर्भ

[7] (4) 1985 पी.एल.जे. 146.

का निर्णय धारा 28-ए को सम्मिलित करने वाले संशोधन से बहुत पहले 20 ☒ प्रैल, 1982 को ☒ तिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा किया गया था। वर्तमान मामले में संदर्भ का निर्णय ☒ तिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा 1 मई, 1987 को, यानी संशोधित ☒ धिनियम के बाद किया गया था। ***मेवा राम बनाम हरियाणा राज्य[8] (8)*** में सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 के ☒ धिनियम 68 द्वारा सम्मिलित धारा 28-ए के दायरे पर चर्चा की और उसके पैरा 5 में निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"इसके ☒ लावा, किसी पुरस्कार को फिर से खोलने के लिए धारा 28 ए के ☒ लावा ☒ धिनियम में कोई प्रावधान नहीं है जो ☒ंतिम और निर्णायक हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि धारा 28ए ☒ ब मुआवजे की राशि के पुनर्निर्धारण का प्रावधान करती है, बशर्ते उसमें निर्धारित शर्तें पूरी हों। इस तरह के पुनर्निर्धारण के लिए, फोरम कलेक्टर है और पुरस्कार की तारीख से तीस दिनों के भीतर उसके समक्ष आवेदन करना होगा, और यह ☒ धिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने ☒ धिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया है। यदि ये शर्तें पूरी होतीं, तो याचिकाकर्ता ☒ धिनियम की धारा 28 ए के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठा सकते थे। उस स्थिति में, धारा 25 उनके लाभ को सुनिश्चित करेगी। कोई भी ☒ न्य दृष्टिकोण विनाशकारी परिणामों को जन्म देगा जो विधायिका द्वारा ☒ पेक्षित नहीं है।"

---

[8] (5) 1986 राजस्व कानून रिपोर्टर 488,

(5) चूंकि याचिकाकर्ताओं ने ☒ धिनियम की धारा 28-ए के तहत जेरेमेद्योव को साबित करने का विरोध नहीं किया, इसलिए निष्पादन न्यायालय ने उस पर विचार करने से उचित रूप से इनकार कर दिया क्योंकि यह इस तरह से बनाए रखने योग्य नहीं था। परिणामस्वरूप, दोनों याचिकाएँ विफल हो जाती हैं और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती हैं।

पी.सी.जी.

☒ स्वीकरण : स्थानीय भाषा में ☒ नुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह ☒ पनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी ☒ न्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का ☒ंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धार्थ कपूर

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फरीदाबाद, हरियाणा